मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 22/07/2025

क्र. IPI/5/0050/2024/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स टीएसीसी लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिरसोदा, जिला देवास में रुपये 1,850.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश (पुनरीक्षित रु. 1,871.00 करोड़) से ग्रेफाइट एनोड निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2209060001) हेतु शासनादेश दिनांक 24.05.2023 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुर्नविलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है-

1. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना को नवीन विद्युत संयोजन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्षो हेतु रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से स्वीकृत छूट के स्थान पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु रूपये 2.50/- प्रति यूनिट की दर से तथा आगामी 5 वर्षो हेतु पूर्वानुसार रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
2. विभागीय आदेश क्र. IPI/05/0032/2023/ए-ग्यारह, दिनांक 24.05.2023 द्वारा परियोजना को स्वीकृत अन्य सुविधायें यथावत रखा जाता है।
3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता हैं।
4. यह आदेश निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 01/07/2025 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(राघवेन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0050/2024 /ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 22/07/2025

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. कलेक्टर, जिला- देवास।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिगनेटरी, Vice Chairman, M/S TACC Limited, Mandideep (Near Bhopal) Madhya Pradesh, Raisen -462046

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग